

## न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 91/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00091)

रूपसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवारी वौरई तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश अति० जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 12.6.2014 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर आदेश दिनांक 06.03.2013 (अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट)

उपरिथित:-

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:- 05.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.6.2014 व नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.65 में से रकबा 0.12 है० वाकै ग्राम वौरई तहसील कुम्हेर पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये निर्णय दिनांक 06.03.2013 से वेदखल कर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया था। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा अति० जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने बाद कार्यवाही अपीलधीन आदेश दिनांक 12.6.2014 पारित करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की है। इस आदेश के खिलाफ उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तहत पत्रावली तलब की गई रैस्पोजेन्ट को तलब किया गया। रैस्पोजेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 व नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 विधिविरुद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को नायब तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर नियत पेशी को अपीलान्ट नायब तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा जवाब हेतु समय चाहा था। इसके बाद अगली पेशी पर



43  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भरतपुर



ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में अहम कानूनी भूल की है। विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का कोई दस्तावेज अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र यह लिख देने से ही की अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, कानूनन मानने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय एडीएम भरतपुर द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अतिक्रमी को बेदखल किया जावे जबकि अपीलान्त को नायब तहसीलदार कुम्हेर के निर्णय की पालना में अपील पेश किए जाने से पूर्व बेदखल किया जा चुका था। जिसकी बेदखली रिपोर्ट नायब तहसीलदार की पत्रावली में संलग्न है। इसके बाद अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया। इसके बावजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विवादित भूमि से बेदखल करने व भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 में निर्देश दिए हैं जो कि कानूनी रूप से गलत हैं। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि विवादित खसरा नंबर 77 रकबा 0.65 है० में से 0.40 है० भूमि ग्राम पंचायत हेतु दिनांक 18.09.2019 को आवंटित कर दी गई है। उक्त भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा वर्तमान में नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 के क्रम में अपीलान्त को बेदखल किया जा चुका है व अपीलान्त द्वारा शास्ती राशि भी जमा करा दी गई है। जहां तक पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो नायब तहसीलदार न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिचार होने का कोई रिकार्ड नहीं है। केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयान को आधार मानकर पश्चातवर्ती अतिचारी माना गया है, जो कि उचित नहीं है। वकील अपीलान्त ने इस संबंध में 1996 आर. आर.डी पेज 583 व 585 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में पूर्व में बेदखल किए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति, घटनाबही की प्रमाणित प्रति आदि संलग्न नहीं किए जाने पर पश्चातवर्ती अतिचार मानकर दिए गए सिविल कारावास के दण्ड को उचित नहीं माना गया है। इसी तरह के सिद्धान्त आर.बी.जे (7) पेज 25-26 पर उद्धरित निर्णय में भी पारित किया गया है। वकील अपीलान्त ने 1996 (3) आर.बी.जे पेज 361 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया कि पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में सिविल कारावास का दण्ड दिए जाने से पूर्व नोटिस में पश्चातवर्ती अतिचार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है तथा अतिचारी को यह मौका होना चाहिए कि वह अपने बचाव में उपयुक्त तैयारी कर न्यायालय में उपस्थित हो सके तथा पटवारी द्वारा दिए गए बयान में जिरह का अवसर प्राप्त हो सके। उक्त प्रकरण में अदालत मातहत में न तो अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया और न ही बचाव हेतु मौका दिया तथा पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयानों में भी जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। इसी तरह पश्चातवर्ती अतिचार साबित किए जाने हेतु पूर्व का निर्णय, विवादित भूमि से बेदखल किए जाने का दस्तावेज प्रस्तुत होना आवश्यक है। इसके अभाव में दिये गए सिविल कारावास के दण्ड को उचित नहीं



५९  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भरतपुर

माना गया। इस तर्क के समर्थन में 1996 (3) आर.बी.जे पेज 410 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। आर.आर.टी 2003 (1) पेज 599 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि यदि पश्चातवर्ती अतिक्रमी रिकार्ड से साबित नहीं है कि उसे पूर्व में कब व किस प्रकार से वेदखल किया गया है तो इस तरह के मामले में सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाना उचित माना गया है। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्त निर्णय दिनांक 06.03.2013 में पारित सिविल कारावास की सजा निरस्तनीय है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने भी उनके समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में इन बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलान्त की अपील को गलत रूप से खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलान्त निर्णय दिनांक 12.06.2014 तथा नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 में पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्त द्वारा की गई वहस का प्रतिउत्तर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलान्त आदेश दिनांक 12.6.2014 व नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्त के द्वारा सम्वत 2069 में विवादित आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 0.65 में से रकबा 0.12 है0 ग्राम बावैन तहसील कुम्हेर चारागाह गेहूं की फसल काशत कर अतिक्रमण किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी अंकित है। रिकार्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं वयान से अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना वखूवी साबित होता है। अपीलान्त ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सके। तहत परीक्षण अदालत ने अतिक्रमी को 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये विधिवत तरीके से सुनवाई उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है, जिसका परीक्षण अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रथम अपील में किया जा चुका है। अपीलान्त सरकारी भूमि पर वार-वार अतिक्रमण करने का आदतन है इसलिए तहत अदालत ने अपीलान्त आदेश से परीक्षण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है। अतः अपील अपीलान्त वेबुनियान्त होने के कारण खारिज की जावे एवं तहत अदालत का फैसला यथावत रखा जावे।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की वहस सुनी गई तथा अपीलान्त निर्णयों संबंधी मूल पत्रावलियों एवं वकील अपीलान्त की ओर से वहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की ओर से अपीलान्त के विरुद्ध आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 0.65 है0 किस्म चारागाह के 0.12 है0 रकबे में गेहूं की फसल बोककर अतिक्रमण किए जाने व कैफियत में अपीलान्त की ओर से गत वर्ष भी अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख करते हुए तहसीलदार कुम्हेर को दिनांक 12.01.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके साथ नजरी नक्शा, खसरा परिवर्तनशील की प्रति प्रस्तुत की। उक्त



५६  
15. 10. 2013  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भरतपुर

रिपोर्ट पेश होने पर अपीलान्त को नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया, जिसमें दिनांक 06.02.2013 को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। नियत पेशी पर अपीलान्त स्वयं उपस्थित हुआ व जवाब हेतु समय चाहे जाने का उल्लेख आदेशिका में किया हुआ है। इसके बाद अगली पेशी दिनांक 28.02.2013 को अपीलान्त की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया गया कि अपीलान्त का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वरन् खातेदारी की भूमि पर कब्जा है। विवादित भूमि की पैमाइश प्रार्थी के सामने कराई जाए। यदि पैमाइश में प्रार्थी का कोई कब्जा सरकारी भूमि पर पाया जाता है तो प्रार्थी उसे हटाने हेतु तैयार है। इसके बाद पर अपीलान्त के उपस्थित नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पटवारी हल्का के दिनांक 06.03.2013 को बयान लेने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2013 को पारित किया गया। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 में दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए अपीलान्त को विवादित भूमि से बेदखल किए जाने, लगान के 50 गुना राशि के अर्थदण्ड पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण तीन माह अर्थात् 90 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। अपीलान्त की ओर से उक्त निर्णय के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई। जिसमें अदालत मातहत द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं किए जाने व दस्तावेजों के बिना दिए गए सिविल कारावास की सजा को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 में यह मानते हुए कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचार माना है। पटवारी हल्का के बयान में भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बखूबी पाया जाता है। अपीलान्त की ओर से विवादित चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होने के संबंध में कोई साक्ष्य/प्रमाण पेश नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि अपीलान्त की ओर से पुनः अतिक्रमण किया जाए तो धारा 91 (2) पश्चातवर्ती अतिक्रमी व धारा 91 (6) एलआर एक्ट के प्रावधान अनुसार तत्परता से कार्यवाही की जावे। वकील अपीलान्त की ओर से बहस में संदर्भित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण किए जाने से यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा विवादित भूमि पर अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिचारी होने के संबंध में पत्रावली में न तो पूर्व निर्णय की पत्रावली संलग्न की और न ही पूर्व में बेदखल किए जाने की रिपोर्ट ही पत्रावली में लगवाई। पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयानों में भी यह उल्लेख नहीं है कि पूर्व में अपीलान्त को विवादित भूमि से कब बेदखल किया गया था। इसके अलावा वकील अपीलान्त द्वारा बहस में यह भी उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि में से कुछ भूमि ग्राम पंचायत हेतु जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 2019 में आवंटित कर दी गई है। वर्तमान में अपीलान्त का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। नायब तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों

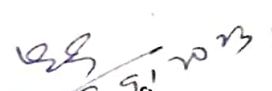


45  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में विवादित भूमि से अपीलान्ट को दिनांक 14.03.2013 को बेदखल किए जाने व उक्त भूमि में बोई गई फसल को नीलाम किए जाने की रिपोर्ट संलग्न की हुई है। अर्थात् अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल किया जा चुका है तथा शास्ती की राशि भी तत्समय ही जमा कराए जाने का वकील अपीलान्ट द्वारा अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर तीन माह अर्थात् 90 दिवस के साधारण कारावास की सजा के दण्ड को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन यह भी सही है कि विवादित भूमि की किरम चारागाह है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित निर्णय के क्रम में चारागाह भूमि को निजी व व्यावसायिक आवंटन/नियमन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार कुम्हेर को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 जिसमें सिविल कारावास की सजा को यथावत रखे जाने के आदेश दिए गए हैं, को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 में विवादित भूमि से बेदखल किए जाने लगान की 50 गुना शास्ती राशि के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने को यथावत रखते हुए पश्चातवर्ती अतिचारी के आधार पर तीन माह अर्थात् 90 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किए जाने की सजा को निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अभी भी अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुए वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में पश्चातवर्ती अतिचारी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान आदि लेने, अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में सभी सुसंगत दस्तावेज प्राप्त करते हुए सिविल कारावास के संबंध में पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखा जाकर आज दिनांक 05.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(साँवर सल्लु वर्मा)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर

